

There will be no 'Question Hour' on these days. There will also be no Private Members' Business on Friday, the 31st July, 1998.

The Committee also allotted time for Government Legislative Business as follows:—

Business	Time Allotted
1. Consideration and return of the Beedi Workers' Welfare Cess (Amendment) Bill, 1998, as passed by Lok Sabha.	1 hour
2. Consideration and passing of the following Bills after they have been passed by Lok Sabha:—	
(a) The Interest on Delayed Payments to Small-scale and Ancillary Industrial Undertakings (Amendment) Bill, 1998.	2 hours
(b) The Oil fields (Regulation and Development) Amendment Bill, 1998.	2 hours
(c) The Export-Import Bank of India (Amendment) Bill, 1998.	2 hours
(d) The Cotton Ginning and Pressing Factories (Repeal) BOI, 1998.	1 hour

#### **RE. DEMAND FOR DISCUSSION ON GOVT'S DEaSION TO PRIVATISE THE PUBLIC SECTOR**

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ghulam Nabi Azad, please.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, I have a submission to make on the Business.

MR. CHAIRMAN: Mr. Azad, please wait. He has something to say on the Business.

SHRI JIBON ROY: Sir, my submission is this. We are discussing so many things here. But there is one important thing for which we have not found time. This is in regard to the Government's decision to privatise almost the entire public sector. Seventy-five per cent is to be disinvested. I had raised this issue in the House sometime back. My colleagues had also raised it. Sir, is it that the puUic

sector workers, numbering twelve lakh, have no right to be heard? The public sector is going to be privatised, without this issue being discussed in the House. I submit to you, I had raised this issue earlier also. I requested you to look into this matter. If this is the position, where would the workers' voice be heard? Does it mean that Parliament has nothing to do with the labour? I submit this for your consideration. Sir.

MR. CHAIRMAN, Now Shri GHULAM NABI AZAD, please.

#### **RE-KILLINGS BY MILITANTS IN DODA**

श्री गुलाम नबी आजाद ( जम्मू और कश्मीर ) : माननीय सभापति जी, पिछले चार महीनों से जम्मू और काश्मीर में और विशेष रूप से सुबह जम्मू के डिस्ट्रिक्ट डोडा में आतंकवाद से जो परिस्थिति बन रही है, उस पर बहुत सारी चिन्ता हम प्रकट करते हैं। मुझे

अफसोस से कहना पड़ता है कि इसी साल अप्रैल में पहली दफा सुबह जम्मू में उधमपुर में 17 अप्रैल को पराकोट में 26 हिन्दू मारे गए मिलिटेंट्स के द्वारा और मैं समझता हूँ कि जम्मू और काश्मीर में यह पहला वाक्या होगा कि इतनी ज्यादा संख्या में एक ही जगह पर, एक गांव में मिलिटेंट्स के द्वारा इतने लोग मारे गए हों। पूरा देश और यह सदन और दूसरे सदन ने भी इस पर अपनी चिन्ता प्रकट की थी। माननीय गृह मंत्री जी वहां गए थे, सीनियर आफिसरज गए थे। हमारी पार्टी की अध्यक्ष मिससेज सोनिया गांधी भी गई थीं, बहुत सारे लोग हम में से वहां थे लेकिन मुझे अफसोस है कि इसके बाद भी कोई खास कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह से इसी साल की 18 जून को उधमपुर के पास में ही जहां से उधमपुर खत्म होता है और डिस्ट्रिक्ट डोडा शुरू होता है, चापनारी में एक दूसरा वाक्या हुआ जिसमें 25 बारातियों को मारा, दिनदहाड़े मारा गया, दिन के डेढ़ बजे 25 लोग मारे गए हों। 23 जून को उसी एक हफ्ते के अन्दर माननीय गृह मंत्री जी वहां गए, सीनियर आफिसरज गए और उन्होंने उनके साथ बातचीत की ओर 24 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी ने श्रीनगर में वहां के गवर्नर, वहां के मुख्य मंत्री, सीनियर सिविल आफिसरज आर्मी और सिक्युरिटी फॉर्सिज के साथ मीटिंग की।

उस 24 तारीख के हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में आडवाणी साहब की मीटिंग की वहां से रिपोर्टिंग होती है-

"Advani Announces Four-pronged Plan to Check Militancy."

इंडियन एक्सप्रेस लिखता है-

"Anti-militancy Pro-development\* are Advani's new J.K. Buzz Words. Advani Owns Responsibility for Massacre."

सर, यह 24 तारीख की बात हुई। उसके बाद 29 तारीख, सिर्फ 4 दिन के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मीटिंग बुलाई। 26 या 27 के बीच में यह तय हुआ कि एक हाई पावर वर्किंग कमेटी का डेलीगेशन माननीय प्रधान मंत्री से मिलें। 29 तारीख को डा० मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 7 वर्किंग कमेटी के मेम्बर्स का डेलीगेशन, जिसमें मैं भी था, माननीय प्रधान मंत्री और माननीय होम मिनिस्टर साहब से, प्रधान मंत्री जी के घर पर मिला और हमने जम्मू-काश्मीर तथा विशेष रूप से सूबा जम्मू में और डिस्ट्रिक्ट डोडा में बढ़ते हुए आतंकवाद पर अपनी पार्टी के तरफ से, देश की तरफ से जम्मू-काश्मीर के लोगों की तरफ से, जम्मू के लोगों

की तरफ डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों की तरफ से चिंता प्रकट की और माननीय प्रधान मंत्री और होम मिनिस्टर से निवेदन किया कि इस पर कुछ न कुछ कार्यवाही की जाए।

उसके बादी कल वह वाक्या हुआ। कल के वाक्य में फिर ठाकराई किश्तवाड़ में 16 आदमी मारे गए। पेपरों ने लिखा है 80-85। वह जिगजैग हैं। पहाड़ में नीचें में जाएं तो बहुत दूर लगता है। यह वह इलाका है जहां 1977 में मैंने विधान सभा का इलेक्शन लड़ा था और इस इलाके को, उस ठाकराई को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यह किश्तवाड़ जो सब-डिवीजन, हेड-क्वार्टर है वहां से पगडंडी से डेढ़ किलोमीटर मेन सिटी से है। घूम घुमाकर शायद 25-30 किलोमीटर होगा। वहा कल के दिन फिर 16 आदमी मारे गए।

माननीय सभापति जी, जैसा मैंने अर्ज किया कि पहले गृह मंत्री जी गए उधमपुर भी गए, चापनारी भी गए चापनारी में गृह मंत्री जी ने बताया था कि आज के बाद कोई वाक्या नहीं होगा। लेकिन एक्जैक्टली उसके एक महीने बाद यह वाक्या हुआ। 17 से 23 जुलाई तक इसी महीने 4-5 रोज पहले तक मैंने खुद डिस्ट्रिक्ट डोडा का दौरा किया। डोडा, भेदवाह, किश्तवाड़, जहां यह वाक्या हुआ, तकरीबन जैसा कहा कि किश्तवाड़ा से अगर आप पगडंडी से जाए तो एक-डेढ़ किलोमीटर है वहां मैं रुका। अपने दौरे के दौरान इन तीनों, चारों के तहसील हैडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स में मैंने खुद सिविल आफिसर्स से, डिप्टी-कमिश्नर से, एस०डी०एम० से, एस०एस०पी० से एडीशनल एस०पी० से और जो दूसरे सेंट्रल पैरा-मिलिट्री के साथी हैं उनसे बातचीत की। उनकी एक ही मांग थी की हमारी वीपनरी को मजबूत किया जाए, हमारे फोर्सों को स्ट्रेंथन किया जाए। मंत्री जी को भी पार्लियामेंट के इनके चैम्बर में बताया। वहां के लोगों की चिंता और डिस्ट्रिक्ट डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन की चिंता और जो मैंने उनसे चर्चा की थी, वह सब मैंने गृह मंत्री जी के सामने रखी थी। मैंने उनसे निवेदन किया था कि वहां फोर्सों को स्टैथन एस० किया जाए।

1995-96 में जब पूरा दबाव मिलिटेंसी का काश्मीर घाटी में था उस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारी फोर्सों डबल थी। आज जबकि दबाव पूरे सेबा जम्मू और डिस्ट्रिक्ट डोडा में है। तो वहां सेंट्रल फोर्सों की प्रेजेस आधी हैं, 1995-96 के मुकाबले में। लिहाजा मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है?

यह खुशकिसमती की बात है कि आज गृह मंत्री जी जो स्वयं काश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं, यहां हैं वरना हम जीरो आवर में यहां खुद ही सुनते हैं और खुद ही बोलते हैं। उस पर कोई एक्शन नहीं होता है।

इन तमाम बातों को नजर मे रखते हुए मैं माननीय गृह मंत्री जी से तीन चीजें पूछना चाहता हूं। 23 जून को आप काश्मीर गए थे जब पहला वाकया हुआ था डिस्ट्रिक्ट डोडा में और 24 तारीख को आपने सिविल और सीनियर आफिसर्स से वहां मीटिंग की थी....। और जिसमें आपने एनाउंस किया था, 'आडवाणी एनाउंसमेंट फोर प्रॉगंड प्लान टू चैक मिलिटेंसी', तो यह 'फोर प्रॉगंड प्लान' का क्या हुआ? उसके बाद उसमें फॉलो-अप कहां तक हुआ? दूसरा जो 29 जून को वकिंग कमेटी का डेलीगेशन माननीय होम मिनिस्टर और माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला जिसमें हमने निवेदन किया था कि इसमें कार्यवाही करें, इसके एक महीने आगे, एक्जैक्टली 29 जुलाई आज हैं, एक महीने में क्या फालो अप हुआ पी0एस0 हाउस से या मंत्रालय से फोर्सेस को स्टैथन करने के लिए, मिलिटेंसी को कम करने के लिए, कंटेन करने के लिए और वी0डी0सी0 विलेज डिफेंस कमेटीज जिनको हथियार दिए गए थे, लेकिन वे हथियार ओब्सोलीट हैं, 303 जिस पर कि मैं आज से 30 साल पहले स्कूल में और कालेज में एन0सी0सी0 की ट्रेनिंग करता था, वही 303 आज मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई करने के लिए दी जाती हैं और खास तौर से विलेज डिफेंस कमेटीज को, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा मज़ाक कोई हो नहीं सकता, जो कि इस बारे में उन्होंने किया और परसों आज से एक हफ्ता पहले माननीय गृह मंत्री जी से वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो चिंता प्रकट की थी उसके बारे में गृह मंत्रालय से क्या कार्यवाही की गई?

माननीय सभापति जी, आज जो कोलंबो में शिखर सम्मेलन चल रहा है और हमारे मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज़ शरीफ से बातचीत करने वाले हैं, मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा अवसर है, इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट डोडा और जम्मू-कश्मीर के लोगों और अपनी पार्टी तथा मेरे ख्याल में दूसरे सदन के साथियों को भी इसमें कोई आब्जैक्शन नहीं होगा, इस सदन के द्वारा, आपके द्वारा माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह मैसेज पहुंचाना चाहिए कि यह सदन और देश जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंट्स का मुकाबला करने के लिए ओर सख्ती से मुकाबला करने के लिए उनके

पीछे हैं, उनके साथ हैं। हम कभी भी उसमें पीछे नहीं रहेगें। जहां तक देश के हित का, देश की एकता का, देश की अखंडता का और देश की स्वतंत्रता को कायम रखने का संबंध है, कांग्रेस हमेशा किसी भी सरकार की सहायता करेगी, मदद करेगी। लेकिन हम सरकार से भी यह अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह भी आगे बढ़े। लेकिन एक कान से सुने और दूसरे कान से अगर निकाल दे तो खाली मदद करने से कोई फायदा नहीं होता। आज हमारे प्रधान मंत्री पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से साफ-साफ बात करें कि मीटिंग तो होती रहती है, फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर होती हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज के लेवल पर मीटिंग होती हैं, पिछले 7-8 वर्षों से यह मीटिंग का सिलसिला तो जारी रहा है। और कभी-कभी प्रधान मंत्रियों की मीटिंग भी दूसरे देशों में होती रहीं, चाहें पहले प्रधान मंत्री हों या आज के प्रधान मंत्री हों, लेकिन जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंसी से कोई फर्क नहीं आया है, मिलिटेंसी बढ़ती गई है। अगर पाकिस्तान एक तरफ से कहता है, हम बात-चीत करते हैं तो तकरीबन जब तक कोई हल नहीं निकलता है, जब तक वह बात-चीत किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकती है, तब तक तो कम से कम मिलिटेंसी बंद हो। लेकिन एक तरफ से वे लोगों को मारें भी एक तरफ से अपने मिलिटेंट भी भेजें, एक तरफ से फॉरेन मर्सेनरीज भी भेजें, एक तरफ से अपने पुराने सिपाही भी भेजें जो पाकिस्तान में आर्मी में हैं और हिन्दुस्तान के गरीब लोगों को मारें और दूसरी तरफ से वह बात-चीत का रास्ता भी खुला रखें, तो मैं नहीं समझता कि ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं। हां, अगर कोई परपज़फुल बात-चीत हो तो हम उसका प्रयोग वेलकम करते हैं। लिहाजा इस सदन के द्वारा मेरे ख्याल में प्रधान मंत्री जी को मैसज जाना चाहिए कि इस दफा इस शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ ठोक बजा कर इस देश की तरफ से बात करें और मिलिटेंसी का खात्मा करने के लिए हमारी बात उन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।

**प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा ( दिल्ली ) :** सभापति महोदय, गुलाम नबी आजाद जी ने जो प्रश्न उठाया है, उस बात पर यह सारा सदन ओर सारा देश अपनी चिंता प्रकट करता है।

सभापति महोदय, कल जो घटना हुई, उस से सारे देश की आत्मा हिल गयी है। सारे देश का मन कांप उठा है। यह घटनाएं पिछले कई सालों से घट रही हैं और यह आतंकवाद पिछले 9-10 वर्षों से हजारों लोगों की बलि ले चुका है। कल 5 व्यक्ति अपहृत किए गए।

महोदय, आहत व्यक्तियों की मौत जिन हालत में होती है, उसे देखकर मानवता की कांप जाती है। जब उन की लाशें मिलती हैं तो उन के कलेजे निकाल लिए होते हैं, उन के कई अंग काट लिए होते हैं, उन की आंखें निकाली होती हैं, उन के गले धीरे-धीरे रेतकर उन्हें मारा होता है या उन को पानी में डुबो —डुबोकर मारा जाता है। महोदय, लोग घरों में बैठे टी0वी0 देख रहे हों, कुछ लोग आएँ और बच्चे, नौजवान व महिलाओं की हत्या कर दें, यह ऐसे लोमहर्षक कृत्य हैं जिन पर कि पशु को भी शर्मिदा होना चाहिए। परंतु जो बात गुलाम नबी जी ने कही, वह बात बिल्कुल साफ है कि इन घटनाओं में आई0एस0आई0 का हाथ बिल्कुल साफ हो जाता है। इन आतंकवाद की घटनाओं से जाहिर है कि पाकिस्तान एक तरह की प्रोक्सी वार लड़ रहा है। महोदय, आप पाकिस्तान टी0वी0 को देखें तो वहां हिन्दुस्तान के खिलाफ युद्ध का उन्माद खड़ा किया जाता है और इन घटनाओं को इस तरह से जस्टिफाई का हनन किया जाता है कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। महोदय, कश्मीर में जिस तरह से मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, अगर उसे ठीक ढंग से दुनिया के सामने लाया जाए तो उस से सारी दुनिया को हिल जाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जब पाकिस्तान के साथ बात हो रही है तो जैसा कि गुलाम नबी जी ने कहाउ सारा देश प्रधान मंत्री के पीछे हैं कि इस संबंध में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से बात होनी चाहिए और जहां हम आपस में संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान काश्मीर में इस आतंकवाद को और प्रोक्सी वार को समाप्त करें। महोदय, जेहाद के नाम पर वहां भाड़े पर कई दूसरे देशों के लोग इस दुष्कृत्य में शामिल हैं। वहां कई भाड़े के सैनिक पकड़े गए हैं, उन की डायरियां पकड़ी गयी हैं और उन से सबूत पकड़े गए हैं जिन से उन घटनाओं के पीछे आई0एस0आई0 का हाथ पूरी तरह से साफ हो जाता है। महोदय, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत के समय इस सवाल को भी उन के सामने रखा जाए कि किस तरह से वहां बेचारे और बेकसूर लोगों की नृशंस हत्याएं की जा रही हैं।

महोदय, इस बारे में फारूख अब्दुल्ला जी के जो वक्तव्य आए हैं और उन्होंने प्रधान मंत्री जी से बातें कही हैं और जिस तरह से काश्मीर के अंदर उन को परिस्थितियों से मुकाबला करना पड़ रहा है, सभी राजनीतिक दलों के लोग मारे जा रहे हैं, उन संबंध में उन्होंने कई सुझाव आप के सामने रखे हैं। महोदय, यह बासत बिल्कुल ठीक है कि अगर वहां लोगों को स्वचालित हथियार दे दिए जाएं तो लोग खुद भी इन का मुकाबला

कर सकते हैं। इन संबंध में एक योजना भी बनायी गयी है जिस के संबंध में गृहमंत्री जी बताएंगे की उन की योजना क्या है? परंतु मैं यह जरूर चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा है और गृह मंत्री जी ने खुद भी कहा था कि उन मरे हुए लोगों को देखकर उन का दिल दहल गया है। मैं चाहूंगा कि उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार की जाए और सारी दुनिया को दिखाई जाए कि पाकिस्तान किस तरह से उन नृशंस हत्याओं में शामिल हैं और सारी दुनिया के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के इस दुष्कृत्य को बेनकाब किया जाए। पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित कराने के लिए प्रयास किए जाए। महोदय, मैं समझता हूँ कि प्रधान मंत्री जी जब वापिस आएंगे तो उन की पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से आतंकवाद के बारे में क्या बाते हुई, उन्हें वह सदन के सामने रखेंगे। महोदय, गुलाम नबी आजाद जी की इस बात का समर्थन करता हूँ कि दोनों सदन और सारा देश इस संबंध में प्रधान मंत्री जी के पीछे हैं और हम चाहते हैं कि वह पाकिस्तान से इस संबंध में दो टूक बात करें।

**SHRI SANTOSH BAGRODIA**  
(Rajasthan): Mr. Chairman, I associate myself with the submission made by Shri Ghulam Nabi Azadji and Prof. Vijay Kumar Malhotraji.

**SHRI M. VENKAIAH NAIDU**  
(Karnataka): Mr. Chairman, Sir, this is an issue—cutting across party lines—on which the entire country should condemn these brutal killings. This is an occasion for us to expose Pakistan in international fora about their subvertive activities that are being indulged in by them from time to time. In the last 20 years, more than 18,000 people were killed in Kashmir. In these killings Pakistan's hand is known to everybody. In the recent days, some of the militants were killed. The mercenaries were identified as people from Pakistan, people from Sudan, people from Afghanistan. These people are being imparted training. They are being given arms and ammunition. They are doing it with a purpose. The purpose is to subvert India, to weaken us and to cripple us economically. This is a grand design of such countries who are inimical to India. They want to weaken our system. They want to subvert our

country. That being the case, we should now take strong steps. I totally agree with Sh'ri Ghulam Nabi Azadji.

I had been to Jammu and Kashmir recently. I met not only my party workers but also other sections of the public. I got, their opinions. Everybody is very agitated, very, very worried. Everyone wants additional forces to be sent to those places, particularly, Dada, Rajouri and Poonch.

Secondly, the Village Defence Committees should be strengthened further. Sophisticated arms should be given to the Village Defence Committees so that they will be able to encounter the militants as and when they attack them.

Another disturbing fact has come to my notice. As you all know, in Punjab, when militancy was at its peak, it was the local police aided by the Indian paramilitary forces that tackled the militancy there. Unfortunately, in Kashmir, the information is that certain elements which are not friendly towards us have also infiltrated into the administration and the police force. This is really disturbing. Unless those people are identified and weeded out of the administration, the local people there who are helpless and always depend on the State administration or the Central Administration, will not be able to fight effectively. Even the Chief Minister and the other leaders have to be guarded by the Central forces. That shows the situation there. The local administration also includes such people who are not willing to fight against the militants. This is one important thing which the Government of India, particularly the Union Home Ministry, should take note of and take steps to weed out such elements from those sensitive positions.

Thirdly, talks are now going on in the SAARC today. This occasion should be utilised by the Government of India and the Prime Minister to convey to Pakistan, in no uncertain term\*, that the entire country is agitated, that we are strongly condemning the happenings. Pakistan

should be told, "Hands off India. We really want good neighbourly relationship with you and we want you to be strong, stable and prosperous; but, at the same time, please do not interfere in India's internal affairs, we will not tolerate this." In this language, it has to be communicated to Pakistan. That is my request. Thank you.

**श्री सतीश प्रधान ( महाराष्ट्र ) :** आदरणीय सभापति महोदय, एक बहुत बुरी घटना कल कश्मीर के डोडा जिले में हुई है, जिसके लिए हम बहुत चिंतित हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह कोई ऐसी पहली घटना नहीं हुई है। अभी तक कश्मीर घाटी में और डोडा जिले में हमारे भाइयों को इन हत्यारों द्वारा मारा जा चुका है। हम उस विषय पर यहां चिंता व्यक्त करते हैं और ऐसा न हो, इस बारे में हम कदम उठाएंगे, ऐसी चर्चा करते हैं। लेकिन फिर भी इस तरह के कांड रुक नहीं रहे हैं। तो मेरा कहना है कि इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रुकतीं, इस बारे में भी हमें थोड़ा सतर्क होकर देखना पड़ेगा। जैसा अभी बताया गया मानवाधिकार के बारे में, इस विषय पर दुनिया हमें हमारे जवान वहां जब आतंकवादियों पर कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टैप्स उठाने की कोशिश करते हैं। तो उनके ऊपर मानवाधिकार आयोग के माध्यम से दबाव डालने को कोशिश की जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ जैसा अभी प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा जी ने भी कहा कि गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी इस विषय पर ऐसी कुछ योजना बनाए जिससे कि वे जो अत्याचार वहां पर कर रहे हैं, वे अत्याचार सब जगहों पर बीड़ियों के माध्यम से पहुंचें, वीडियों के माध्यम से दिखाए जाएं और लोग समझें कि आतंकवादी वहां पर इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं और उन्हें यदि बंद करना है तो उनके ऊपर भी मसल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

मसल पावर का इस्तेमाल उनके विरुद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उसमें किसी को रूकावट डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब उस मसल पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, तभी कुछ हो सकेगा। महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अभी कश्मीर में हमारे जवानों ने आतंकवादियों के पास से कुछ हथियार पकड़े हैं और हथियार पकड़े गए हैं, उनकी प्रदर्शनी यहां

लगी हुई थी और उसकर डिटेल्स यहां उपलब्ध हैं। वह सब देखने के बाद आपको पता लगेगा कि जो हथियार बरामद किए गए, वे हथियार 2 डिवरजनों के लिए पर्याप्त थे। मतलब यह कि 11,000 अधिकारियों और जवानों के लिए वे हथियार पर्याप्त थे। इतने वैपंस और एम्बुनिशन उनके पास तो बरामद किए गए हैं। हम सरकार को बार-बार इस बारे में बताते हैं। आज आडवाणी जी गृह मंत्री हैं, पहले जब वह दूसरे गृह मंत्री थे, तब भी हमने बताया था और हम हर समय इन्हें बघताते थे कि उनको आई0एस0आई0 का सपोर्ट हैं और इसके सबूत ऐनेक्सी में लगी प्रदर्शनी में देखे जा सकते थे। यह सब होने के बाद भी हम एक्क्रॉस दि टेबल चर्चा कर रहे हैं कि आप ये रोको-रोको।

महोदय, मैं आपके माध्यम से आडवाणी जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी श्रीलंका गए हुए हैं। वे वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलकर बात करने वाले हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि आप उनको साफ-साफ बता दीजिए कि यह सब रोकने की इच्छा है या नहीं? आप उनके सामने सबूत रखकर बात करो कि यह सब आपके यहां से हो रहा है। आप इसे बंद करने वाले हो या नहीं? अगर बंद नहीं करने वाले हो तो उसके लिए हमें क्या कार्यवाही करनी पड़ेगी, इस पर विचार करने की आवश्यकता है और उसी ढंग से कदम उठाने की आवश्यकता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि यह कभी बंद हो सकेगा। इसके लिए उसी ढंग से उनके विरुद्ध हथियार लेकर हमें खड़ा होना पड़ेगा।

महोदय, आखिर मैं मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब करने के बाद यदि हमारे वहां रहने वाले भाई लोग हाथ से सॉफैस्टिकेटेड हथियार लेकर सामने खड़े होते हैं और हमारी पुलिस के हाथ में 303 हो तो काम नहीं बनेगा। उन लोगों के हाथ में हथियार हैं, वही हथियार हमारे लोगों के हाथ में भी होना चाहिए। जब इस ढंग से उनको जवाब दिया जाएगा, तभी यह बंद होगा नहीं तो यह बंद होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी सरकार को सतर्क होकर इस बारे में कोई कदम उठाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सदन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश इस विषय में आपके साथ होगा, इतना कहकर मैं अपनी बातें समाप्त कर रहा हूं।

SHRI E. BALANANDAN (Kerala): Sir, this is a serious question we are now discussing. Everyone in the House is worried about it. Since the Home Minister is here, I want to inform him about the massacres that had been taking

place since April, 1998. The first massacre took place at Udhampur on April 26 in which 26 people had been killed and the second massacre took place at Doda on June 25 in which another 25 persons had been killed. Yesterday, this distressing incident took place. I want to know exactly what steps the Government is taking to see that the life of the people is protected and their confidence is restored. If it goes on this way, then the people will totally lose their confidence. I want the Home Minister to come and tell us—he is here luckily what steps he has taken from April 26 onwards till date and what protection is being given to the people. I want to have a statement from the Home Minister so that we all are educated. We will in one voice protest against this kind of cruelty being committed against unarmed citizens. This is the fate of the people. The Home Minister should see to it that all types of protective measures are taken to guard the life of people in Kashmir Valley.

**प्र० रामगोपाल यादव** (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने जो मामला उठाया है उससे अपने को और दल को सम्बद्ध करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि निरन्तर यह घटनाएं एक इलाके में हो रही हैं। हम लोग जानते हैं कि स्थानीय पुलिस होती है उसको इस तरह के अपराध करने वालों की जानकारी भी होती है वह कहां रहते हैं हाईडआउट्स क्या हैं, उनकी भी जानकारी होती है। ऐसा लगता है कि हमारे जो बी0एस0एफ0 के और आर्मी के लोग हैं उनको सही सूचना स्थानीय पुलिस के द्वारा नहीं दी जा रही है, वरना कोई वजह नहीं कि तमाम पुलिस बल के रहने के बावजूद, पैरा मिलिट्री फोर्स के रहने बावजूद इन घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। एक तो मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी इस बात को भी जानने की कोशिश करें कि क्या हमारे पैरा मिलिट्री फोर्स को, आर्मी के लोग को स्थानीय पुलिस का सही सहयोग मिल पा रहा है? अगर ऐसा होता तो कोई वजह नहीं कि यह लोग ऐसी घटनाएं बार-बार कर सकें। दूसरे, बहुत दिनों से मामला पड़ा हुआ है। हमारी पंजाब और से आने वाले लोग बंद हैं। लेकिन जो काश्मीर की सीमा पाकिस्तान से मिलती है उस पर हमारा मेटेरियल पड़ा हुआ है, सारा सामान पड़ा हुआ है लेकिन वह बाड़

नहीं लग पर रही हैं। अगर हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट पूरी इच्छा शक्ति के साथ कि जब रोज लोग मारे ही जा रहे हैं और यह बढ़ता ही जाएगा और सारी दुनियां जानती हैं कि पाकिस्तान सरकार के इशारे पर हैं। आई०एस०आई० वगैरह छोड़िए-आई०एस०आई० क्या है it is the Pakistan Government. पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। अगर यह नहीं रुकेगा तो अंतिम परिणति युद्ध के रूप में होगी दोनों देशों की। तो वह स्थिति आए हमें सख्ती से कम जो हमारा एक प्लान है उसकी इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई उधर से इधर न आ सकें, सीमा पर जो तारों की बाड़ लगाने का इरादा है उसमें मजबूती से अमल करना चाहिए, मैं माननीय गृह मंत्री से मांग करना चाहता हूँ।

SHRI S.R. BOMMAI (Kamakata): Sir, I associate myself with the sentiments that have been expressed by the hon. Members here. This is a vexed problem which we have been facing during the last decade. It is absolutely necessary to give protection to the people of Kashmir, particularly of Jammu and Doda districts, and to see that no repetition of such acts takes place. I appreciate the sincerity and the Tomptness with which the Home Minister had acted. After the incident he personally visited there. If there is any plan, if it can be disclosed to the House, the House can be informed about the details. If you want to keep it as a secret and act, we welcome that also. But no repetition of such incidents should take place. Keeping that Border Security Force, the paramilitary forces and the Army on alert is not sufficient. We have to take the people of Kashmir into confidence. They are divided. A section of the people are colluding with the terrorist forces and part of the administration is also colluding with the terrorist forces. This should be eradicated. Otherwise, it is very difficult to control such incidents. Sir, I visited Kashmir myself as party Prudent and as Minister. I met the people. We have to create a climate of confidence and convince this section of the people who are colluding with the anti-national forces and Pakistani forces.

Open a dialogue with them. How it should be done and when it should be done, it is for the Government to decide. I would like to make one more suggestion. Let us, start a people-to-people contact between Pakistan and India. Non-official delegations, intellectuals, lawyers, doctors, etc. should intensify people-to-people contact so that an opinion can be built up in Pakistan (*Interruptions*). I am saying that there should be a people-to-people contact between Pakistan and India. People-to-people contact is a must. Public opinion should be built up in Pakistan so that it can influence the Government of Pakistan.

Let the Prime Minister take a firm stand. We are all with him so far as this issue is concerned.

Thank you.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, two days back I had been to Jammu. I had an occasion to have a discussion with some political leaders of that area. They said that the people living in that area are always living in terror and horror. They also said that those persons, who were in a position to, go to some other place, vacated that area and went to a safer place; whereas those persons, who could not afford to leave that place or who were constrained to live there with their little holdings, were living there in terror.

Yesterday, in the massacre which took place in Doda, they killed 23 persons. I think it is not political<sup>1</sup> motivated. It is just a 'tit for tat'. They are playing with the lives of the people. If asked, "Why, was the situation in the border areas like this?" They said Pakistan wants that the political climate should be in their favour so that they can use this situation as a leverage for their political advantage. That is the situation there. The innocent persons of India should not be made victims. Our Prime Minister, when he meets the Prime Minister of Pakistan in Colombo, should say in clear terms that India will not tolerate this kind of torture.

and terror emanating from Pakistan. I would request the Government to take effective steps to see that the life of the poor people living in that area is safe.

« श्री गांधी आज़ाद ( उत्तर प्रदेश ) : धन्यवाद सभापति महोदय। काश्मीर में जो जघन्य घटनाओं के द्वारा समूह का समूह दिन कत्ले-आम किया जा रहा है, इसकी मैं अपनी और से और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ओर से घोर निन्दा करता हूँ। महोदय, घटनाओं के पुनरावृत्ति में ये बातें आती हैं कि आई०एस०आई० का हाथ है यहां विदेशी आपराधिक एजेंसियों के द्वारा घटनाएं कराई जा रही हैं, यह बहुत ही निन्दा की बात है किंतु मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जब आई०एस०आई० के लोग सक्रिय रूप से आपराधिक घटनाओं को करते हैं और घटना हो जाने के बाद हमारी ,खुफिया एजेंसी को यह एल०आई०ओ० या सी०आई०डी० या सी०बी०आई० के लोगों को पता चलता है कि आई०एस०आई० का हाथ है या किसी आपराधिक संगठन का हाथ है तो यह हमारी एल०आई०ओ० और जो खुफिया एजेंसी हमारे देश की हैं, यह क्यों नहीं इस घटना का पहले ही पता लगा लेती हैं कि इसमें आई०एस०आई० का हाथ है या किसी भी आपराधिक संगठन का हाथ है, तो उसकी पूर्व-योजना को ही विफल कर दें? हमारे देश की खुफिया एजेंसी अगर इसका पता लगा ले और पूर्व नियोजित आपराधिक कार्यों को विफल कर दे तो मेरी समझ में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और मैं समझता हूँ कि यह हमारी कमजोरी का परिचायक है कि सही समय पर सही आपराधिक घटनाओं का पता लगाने के हमारे देश की ,खुफिया एजेंसी पूरी तरह से विफल हैं। इसी के कारण अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। अतः मैं माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ कि हमारे देश की खुफिया एजेंसी को मजबूत एवं सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य किए जाएं एवं हमारी ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाए, वह उन्हें उपलब्ध कराए जाएं ताकि इन अपराधों की पुनरावृत्ति न हो सके।

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA (Uttar Pradesh): Sir, while associating myself with the views expressed by Shri Ghulama Nabi Azad, I want to share with the House, through you, and with the hon. Home Minister my experiences in Punjab.

Sir, it is clear from such incidents that people across the border have a clear strategy, a one-point programme, that is, the programme to destabilise the country, and the strategy is to create chaos in India. Innocent people have always been made victims of such people and soft-targets are attacked. I don't share with the view or I don't support the view of the hon. Member that our intelligence agencies have failed. They have not failed. They are doing their duty well. In Punjab also, there was such a situation. I don't want to refer to those unfortunate incidents here. Some people said that one community was responsible for it. It is wrong. In Punjab, the success started only when information from common man started pouring into enforcing agencies, law and order maintenance agencies. I only urge upon the Home Minister that he must find out why the co-operation of the common man is not available in Kashmir. Then, I would like to know what the reasons are as to why information from common man is not available to the enforcing agencies, the law and order maintenance agencies. Some measures must be adopted and steps must be taken to see to it that information started coming in. It is only because of this that there was success in Punjab. And I am sure that we will succeed in Kashmir as well. So, I associate myself with the views expressed by Mr. Ghulam Nabi Azad.

श्री खान गुफरान जाहिदी ( उत्तर प्रदेश ) : चेयरमैन साहब, मैं अपने आपको इस रंगीन मसले के साथ, जिसको गुलाम नबी आज़ाद साहब ने और हमारे दूसरे मौजूद मैम्बरान ने उठाया है, अपने को संबद्ध करते हुए 2-4 बातें कहना चाहता हूँ, जनाब-ए-आली, कश्मीर में आम हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं, इन वाक्यात के बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं, वहां की मुस्लिम औरतों को रोते हुए देखा गया है, तकलीफ से तड़पते हुए देखा गया है, मकसद यह है कि इसी वक्त जब कि हमारे मुल्क के प्रधान मंत्री अटल जी वहां मिल रहे हैं, उस मुल्क के नवाज़ शरीफ साहब वहां आ रहे हैं; हमारे वज़ीर —ए-आज़म से वह मिल रहे हैं, ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान ने, जिसने प्रॉक्सी वार



वहां शुरू कर रखी हैं, वह इस तरह की मीटिंग का गलत इस्तेमाल करना चाहता हैं। एक तरफ नारा-ए-अमन भी हैं, दूसरी तरफ जंग की तैयारी भी। वह अमन की बात है भी करना चाहते हैं और जंग के लिए भी इस तरह से प्रॉक्सी वार करने की कोशिश करते हैं। इसका एक सियासी मकसद हैं। इस दहशतगर्दी के पीछे एक सियासी मकसद हैं और व हयह है कि इस दहशतगर्दी के जरिए से दो कौमी नजरियों को हिन्दू-मुस्लिम के बीच के निफाक पैदा करना, पाकिस्तान-हिन्दुस्तान की आम जनता के बीच में एक फर्क डालना, एक ऐसी फिजा पूरे मुल्क में क्रिपट करना ताकि तशदुद फूट पड़े, कयास हो जाए, फिरकावाराना बुनियादों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए। हमारे देश में संगीन हालात पैदा करने के लिए पाकिस्तान की ओर से मुसलसल इस तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं।

डोडा में और उसके आसपसा वाकियात जिस तरह से गुजर रहे हैं उससे जह जाहिर होता है कि वाकई हमारी आर्मी इंटेलीजेंस और पुलिस इंटेलीजेंस जो हैं वह पूरी तरह से फेल हो गई हैं। हमें तो अफसोस यह होता है कि माननीय होम मीनिस्टर साहब ने अप्रैल के बाद वहां पर जो एलानात किए और आप एक दो बार वहां गए और आपने कहा कि हम इस तरह का चारनुकाती एक फैसला दे रहे हैं, एक एक्शन प्लान दे रहे हैं, मैं तो यह समझता हूं कि इस तरह के वाकियात अगर अब भी हो रहे हैं तो वह एक्शन प्लान फेल हो गया हैं और उसकी कोई ठेसियत अब नहीं रह गई हैं, वह पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं। सच्ची बात यह है कि वह वजीरें आला, जो उस रियासत का हैं क्योंकि यह कांक्रिट सब्जेक्ट है अगर वह अपने मुल्क की, अपने इलाके की अक्लियतों की हिफाजत नहीं कर सकता हैं तो अच्छा होता अगर फारुख अबदुल्ला साहब इस्तीफा दे देते। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन बार अगर इस तरह के वाकयात मुसलसल होते हैं तो अक्लियतों की हिफाजत में वह नाकाम हो गए हैं इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी तरह से हम समझते हैं कि हो मीनिस्टर साहब ने अगर वहां पर यह फैसला लिया था, मैं जज्बात में यह बात नहीं कहा रहा हूं बेहतर इकदामात नहीं हुए और यह सिलसिला फिर दुबारा हुआ तो उनको इसके बारे में अफसोस का इजहार करना चाहिए और आइन्दा ऐसी इकदामात करना चाहिए, इस्तीफा तो उनको भी देना चाहिए अगर वह नाकामी महसूस करते हैं। लेकिन अगर वह ऐसा महसूस करते हैं

कि नहीं, हमने किया लेकिन हुआ नहीं तो उसके लिए फिर उनको ऐसे इकदामात करने चाहिए जिससे काम हो। साथ ही साथ सारा मुल्क आज यह चाहता है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम जो आपस में मिल रहे हैं वह जंग से नहीं अमन में बैठकर के अपनी बातों को तय करें और एक अच्छे फैसले पर पहुंचे ताकि इस तरह क वाकियात जो कश्मीर में हो रहे हैं और इन्सानियत का कत्लेआम हो रहा हैं, दर्दनाक सुरतेहाल हैं। इन्सानों का कत्ल हो रहा हैं। हम सब के दिल जज्बात से भरे हुए हैं, हमें बे-पनहा अफसोस हैं, उसका इजहार करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि वह कामयाब हों। अगर कामयाबी नहीं होती है तो पाकिस्तान में जहां कि दहशतगर्द उगते हैं और आते हैं और वह जज्बात यहां फैलाए जाते हैं उसके खात्मे के लिए कोई मुस्तकिल प्लान बनाना चाहिए ताकि इस तरह से पाकिस्तान हमारे घर में आस कर, दाखिल हो कर हमारे मामलात को खराब न करें। मैं इन अल्फाज के साथ अपने आपको दूसरे साथियों के जज्बात से संबद्ध करता हूं।

**श्री गया सिंह ( बिहार ) :** माननीय सभापति जी, मैं गुलाम नबी आजाद जी का समर्थन करते हुए गृह मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि पूरा हाउस आपके साथ हैं और आपकी सरकार आने से जम्मू-काश्मीर के लोगों को उत्साह हुआ था और उनके अन्दर यह भावना बनी थी, कई अखबारों में यह चर्चा हुई कि पटेल साहब के बाद आडवाणी जी होम मीनिस्टर बने हैं, अब यह तो लोहा हैं, कुछ करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप फेल हो चुके हैं और आपने जितने जोर से इस हाउस में पीछे कहा था जब ऐसी घटना हुई थी तो लोगों को लगा था कि कुछ कार्य योजना आपकी ऐसी हं जिससे अब काश्मीर में दुबारा ऐसी घटना नहीं होगी। कल जो घटना हुई हैं उसकी जितनी निन्दा की जाए वह कम हैं। उसकी पूरा देश निन्दा करने के लिए तैयार हैं और कर रहा है लेकिन गृह मंत्री जी को महसूस करना चाहिए और हाउस के सामने कहना चाहिए कि आपने जो वायदा किया वह कहां पर फेलियोर हैं, उसकी चर्चा करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आपकी आर्मी की इंटेलीजेंस हैं, आपकी बार्डर सेक्योरिटी फोर्स है उसका अपना इंटेलीजेंस हैं और जैसा आपने कहा था कि दुबारा घटना होने के पहल इसकी जानकारी होनी चाहिए। परन्तु आपकी ये एजेंन्सियां फेल्योर हुई हैं। यह पहाड़ में हैं और सिटी से बहुत नजदीक हैं। यह घटना एक गांव में नहीं हुई हैं। एक गांव में तो घर से निकालकर उनको मारा उसके बाद फिर दूसरे गांव में भी जाकर मारा और इसमें काफी

समय लगा। इस प्रकार आपकी एजेंसीज फेल हुई हैं। इसलिए हाउस के सामने आपको यह कबूल करना चाहिए और यह वायदा करना व. चाहिए... हाउस आपके साथ हैं, देश आपके साथ हैं आपके जो करामात में वह कब निकलेंगे, चार महीने का समय हो गया और काश्मीर में लोग मर रहे हैं। लोगों ने कहा था कि यह सरकार बनी हैं, अब हम अपने घर लौटेंगे। आपने भी कहा था कि उनको घर लौटायेंगे। अब घर लौटाने के बजाए पुनः वहां से लोग भागना शुरू करेंगे। यह बहुत दुखद चीज है, दुखद घटना हैं। हम समझते हैं कि होम मिनिस्टर को इसको गम्भीरता से लेते हुए हाउस को कांफिडेंस में लीजिए, देश को कांफिडेंस में लीजिए और हम लोगों को यह बताये कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं फिर नहीं होंगी।

DR. KARAN SINGH (Jammu and Kashmir): Sir, having represented the Udhampur constituency in the Lok Sabha for 18 years, I fully support the line taken by my friend and colleague Shri Ghulam Nabi Azad in expressing deep pain, anguish and sorrow at what is happening there. Sir, the people living in that area are simple patriotic folks. They are now living under a cloud of terror. The terror is palpable. They cannot sleep at nights. One never knows when and where the next strike is going to be. Let me point out one clarification. My dear friend Margabandu talked about the border. Doda is nowhere near the border. Doda is 300 kilometres from the border. I think the House should realise that it is not a border incident. Quite evidently these people have come in in an organised manner. They are living within the State and then they are able to strike. It is not a hit and run situation at all. It means very clearly, that these groups of highly armed and highly motivated militants are residents in those areas and can, therefore, choose the place and time at which they want to strike. I think, the House should be aware of the gravity of the situation. The situation is that we have been unable to deal with people who have been living in the area under our control now for several years. The first thing, of course, \*,"? do is to try and stop

the ingress. The question arises, how do they get in? Why can we not do something more effective to stop the ingress?

The second question that arises is that once they are in and once they are operating there — I think, it is generally known in which areas they are operating—why are we unable to do anything about it? Sir, I would suggest on thing. I do not want to go into the broader problems and question related to Jammu and Kashmir, on some other occasion we can do that. The Prime Ministers are meeting today in Sri Lanka. One can only hope that something positive -will come out of it. But, immediately whatever may be the result of the SAARC Summit, we have to gear ourselves up in such a way that there is a rapid reaction. My view is that in areas that are sensitive, for example, in Kistwar, in Bhadrwah, in Doda, in Ramban and in Gul-gulabgarh, there should be rapid reaction forces immediately available. They should be available on telegraph so that they can react immediately and some specific action can be taken.

Sir, 20 years ago, we made a suggestion, and Ghulam Nabi will remember, that a cantonment should be constructed at Bhadrwah. The land was also acquired. For some odd reasons which I cannot understand, no steps were taken to construct that cantonment in Bhadrwah.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Land has been acquired for that purpose.

DR. KARAN SINGH: The land has been acquired. I know, I was there. I know every inch of that area like he does. Why was it not taken up? If you have had a proper cantonment in Bhadrwah by now, you would have been able to have a much better reaction.

Secondly, Sir, I must say I have just come back from Leh yesterday. Our Armed Forces are doing a magnificent work.

But, there seems to be a definite plan to activate the entire line of control, there has been shelling in Kargil over the last

one or two days; there have been softie casualties. In the Kargil town, shells have landed in the town and the whole atmosphere is sought to be disturbed. We have to have a proper liaison between the Defence forces, the paramilitary forces, the State administration, the police, and the local citizens. This is lacking. I must say regretfully that there is no proper coordination between all these forces as a result of which nobody is taking the responsibility. First of all, I would express on behalf of all of us our deep anguish. Can you imagine. Sir bridge-rooms going to be married being massacred along with the *barat* on the way? What greater crime can there be against humanity? Is this the way to further a religious cause or a political cause? So, we express our deep sympathy, and I hope that effective steps will be taken. It is no use saying that you will never allow another incident to take place.

1.00 P.M.

I am afraid even if you do say that, I would not take it at its face value because as long as you have those people operating there, they can strike at any time and at a point of their choice. But, what I would like to know from the Government is: How is that these people are operating there almost without any check? Why is it so that we cannot do something effective about it?

**मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी ( उत्तर प्रदेश ) :** चेयरमैन साहब, जनाब नबी आजाद के जरिए जो मसला उठाया गया है मैं उससे अपने को वाबिस्ता करते हुए हिन्दुस्तान के और इंसानियत के दुश्मनों को अपनी पार्लियामेंट और अपने ऐवान से यह कहना चाहता हूँ कि :

[[हिन्दू का कत्ल है न मुसलमानों का कत्ल है,

ए दुश्मनाने हिन्द यह ईसा का कत्ल है]] ।

इस प्रकार की वारदातें रोजमर्रा मामूल बन गई हैं। बहुत बातें हमारे साथियों ने कह दी हैं। मैं उन तमाम लोगों को खिराजे अकीदात पेश करता हूँ जो जुल्म के शिकार हुए हैं और अपने फर्ज से कोताही करने वाले या फराएज को न पहचानने वाले लोगों से यह कहना चाहता

हूँ कि मुल्क की आजादी की रखवाली इस तरह से की जा सकती है जिस तरह से मुल्क को आजाद करवाने के लिए लोगों ने दारों रसन का फुंदा चूमा था। जितनी कुर्बानियाँ मुल्क को आजाद करवाने के लिए दी गई हैं, उससे ज्यादा कुर्बानियों की जरूरत आन पड़ी है, मुल्क की आजादी और खुदमुख्तारी की हिफाजत के लिए हम में से सारी पार्टियों के लोग, इस सोगवार घटना के लिए अपने उन मजलूम, दुनिया से जाने वाले लोगों का शोक मना रहे हैं और दरिन्दों की मज्जमत कर रहे हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि बार्डर पर सिक्थोरिटी फोर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान से आने वाले ये आतंकवादी आसमान से तो नहीं टपकते हैं। जाहिर है कि ये जमीन से चलकर आते हैं और अगर हम भारत की सरहदों की हिफाजत की कसम खाते हैं तो हमारी कसम कहां टूट रही है, हम पर सवालिया निशान लगे बगैर नहीं रह सकता। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगता हूँ, लेकिन मैं किसी पर उंगली न उठाते हुए यह जरूर कहना चाहूंगा कि पुलिस का काम है कि शहरों में फौज या पैरा-मिलिट्री फोर्सेस को आतंकवाद के बारे में खबरदार करना। खुफिया एजेंसी का यह काम है, उसे यह जरूर करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि वह इसे जरूर कर रहे होंगे। मगर बार्डर पर जो फोर्स हुई हैं, जिस बार्डर से हमारे दुश्मन मुल्क में दाखिल हो रहे हैं तो आखिर बार्डर पर वे कौन से काम में लगे हुए हैं जिसकी वजह से दुश्मन हमारे मुल्क में दाखिल होने से कामयाब हो रहा है? दुश्मन यहां आकर नफरत का माहौल पैदा कर रहा है और चाहता है कि सारे बार्डर पर नफरत का माहौल पैदा हो, कश्मीर में नफरत का माहौल पैदा होगा तो तास्सुब की घटायें उठेंगी और खून का पानी बरसेगा इस नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए जरूरी काम मुसस्सल पुरानी गवर्नमेंट में भी होते रहे और यह गवर्नमेंट भी कररे की ख्वाहिश रखती है और आज दोनों प्रधानमंत्री श्रीलंका में इकट्ठे हो रहे हैं। श्रीलंका में दोनों प्रधानमंत्री इकट्ठे हो रहे हैं। चूंकि जो दोनों आवाम परेशान हैं, यहां की आवाम भी परेशान हैं, पाकिस्तान की आवाम भी परेशान हैं। इंसानों में मजलूमियत जो सर उभार रही है, जुल्म के जरिए, इस बारे में कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बातचीत तक ही यह सारा मामला फिर मुझे लगता है, कि महदूद रह जाएगा। मैं नहीं समझता कि हुकूमत के अंदर कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी शक्ति है या कोई ऐसा फैसला करने का मूड है जिसकी बुनियादी पर पाकिस्तान को दो-दो-चार में बात समझाई जा सके। पाकिस्तान केवल बातों के जरिए

समझने वाला नहीं हैं। पाकिस्तान मसलेहत के जरिए समझने वाला नहीं हैं। पाकिस्तान खुशअखलाकी और खुशकिरदारी के जरिए समझने वाला नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ ताकत की जुबान से आपको बात करनइ होगी। अगर आप ताकत की जुबान में बात करेंगे तो हम यकीन के साथ आपसे कहना चाहते हैं कि मरीजे इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। मैं नहीं समझता कि इस तरह से कंट्रोल हो जाएगा और ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि कल भी हमें शोक मनाना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से बयान देने के बावजूद हम जिस तरह से लावार हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, बेकस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं।

इस मजबूरी में एक तरफ हम न्युक्लियर बम का मुताकहिरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ दुश्मन ने हमें चूहा और बिजली समझ लिया है। जब दुश्मन चाहता है तब हमें ललकार देता है, जब दुश्मन चाहता है हमारी सरहदों पर हमला करता है। 11-12 साल से यह जो सर्द जंग हो रही है इसमें मालूल नहीं कितने हिन्दुस्तानियों का खून पानी की तरह सस्ता करके बहवा दिया गया है। मैं आपसे नहीं कहता कि आप जंग कीजिए मगर आप विल पावर के जरिए आप अपनी ताकत के जरिए आपकी नेगोसियेशन में, आपकी बोली में गोली से ज्यादा ताकत होनी चाहिए जिसकी बुनियादी पर आपका दुश्मन सहम कर झुकने के लिए मजबूर हो। मानवता को ललकारा जाना, हिन्दुस्तान के लोगों को इस तरह से बेआबरू करना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। सारी दुनिया में हिन्दुस्तान अमन का हामी रहा है। अभी अभी गुफरान जाहिदी साहब कह रहे थे कि एक तरफ नजरिया-ए-अमन की बात हो रही है दूसरी तरफ जंग का रास्ता पैदा किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नजरिया-ए-अमन तो हमारे पास है और अखबारे-ए-जंग पाकिस्तान के पास है। वह तो पेपर में भी अगर मुफ्तगु, करते हैं। सर, जहां तक हिन्दुस्तान और जम्मू और कश्मीर के तहफुजो वकार का सवाल है मैं अपने ख्यालात का इजहार इन अल्फाज में करना चाहूंगा कि गैरों को मये गंगोजमन दे नहीं सकते। अगर पाकिस्तान यह चाहता है कि कश्मीर को हड़प कर लेगा, अगर हिन्दुस्तान में अफरातफरी पैदा कर के हिन्दुस्तान को मुतज़लज़ल और गैर मुस्तहकिम कर देगा तो हम तमाम पार्टियों के लोगों को पार्टी से ऊपर उठ कर पाकिस्तान के इस नापाक खाब को किसी भी कीमत पर

शर्मिदां-ए-ताबीर नहीं होने देना चाहिए और हर हाल में उसको कह देना चाहिए कि गैरों को मये गंगोजमन दे नहीं सकते। हम दुश्मन को गंगा जमना का पानी नहीं देंगे।

गैरों को मये गंगोजमन दे नहीं सकते,

हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते,

कश्मीर बड़ी चीज़ है क्या देंगे किसी को, हम देश

के दुश्मन को कफन दे नहीं सकते।

इसलिए हमें बड़ी ही मित्रता और समाजत के साथ अपने हुक्मरानों से कहना है जो लोग आज हम फर्ज से सुबुकदोष होना चाहते हैं, हम मुकम्मलतौर पर आपके साथ हैं। हर कदम पर देश के तहफुज के लिए तन, मन और धन के साथ पूरा हाउस। पूरा देश आपके साथ है मगर ,खुदा के लिए आप अपनी मर्दानगी दिखलाइये, आप मैदान में आइये। आप इस तरह की हिन्दुस्तान की तौहीन करने वालों की ज़बान का लगाम दीजिए और अगर मुल्क इसी तरह से टूटता रहा, आतंकवाद इसी तरह से बढ़ता रहा तो कल आने वाले दिनों में मुल्क के आवाम किसी भी हकूमत पर भरोसा करने के लिए आवाम को हथियार दे दिये जाएं। मैं सहमत हूँ इस बात से। मगर आवाम को हथियार देने से पहले उन्हें ट्रेनिंग भी देनी होगी। बिना ट्रेनिंग के आवाम क्या हथियार चलाएंगे? अगर आवाम को ही हिफाज़त करनी है तो पुलिस का हथियार किस काम का है? पुलिस से हथियार जब्त की लीजिये और आवाम को हथियार दे दीजिए। फौज से हथियार छीन लीजिए और आवाम का हथियार दे दीजिए। पैरा सिक्युरिटी फोर्स से हथियार ले लीजिये और आवाम को हथियार दे दीजिये बार्डर सिक्युरिटी फोर्स से कह दीजिए कि घर जाकर बैठे और आवाम को कहिये कि अपने घरों से बार्डर पर जा कर बा हैसियत बार्डर सिक्युरिटी फोर्स का काम करें। यह वश मज़ाक है? इतनी फौज किस लिए है? इतनी पुलिस किस लिए है? क्यों आवाम हाथों में बंदूक लेंगे? क्यों पब्लिक बंदूक लेकर दुश्मनों का मुकाबला करेगी? यह दिन उस वक्त आएगा जब हमारे पास फौज नहीं होगी, जब हमारे पास बार्डर सिक्युरिटी फोर्स नहीं होगी। आज हम इन मामलों में दुनिया की किसी भी ताकत से कमज़ोर नहीं हैं। आवाम अपनी ताकत के साथ, अपने दिल के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपनी सलाहियत के साथ, अपनी काबिलियत के साथ, अपने तन-मन और धन के साथ इस फोर्स पर फ्रक करते हुए उसके साथ होंगे। मगर हज़ूरमुझे अर्ज़ यह करनी है कि हकूमत को एक्टिव होना चाहिए। सिर्फ नारा लगाना, दावा करना

اور دلیل کے نام پر خوب لے ہو جانا، اس میں  
مُلک نہیں بچ سکتا ہے۔ سب لوگوں کی چیتا ہے، ہم  
بھی اس چیتا میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، آپ آگے  
بڑھیے، مردانہ طور پر فیصلہ کیجیے، عشا اللہ  
ہم کبھی بوجھل آپ کو ثابت نہیں ہونے دیں گے۔  
مُلک پورا آپ کے ساتھ رہے گا اور مُلک کے وکیل  
کا سوا کسی بھی دشمن کی عداوت ہرگز نہیں  
کے سکتے۔ شکریہ۔

مولانا عبید اللہ خان اعظمی:

ہمارے: چیئرمین صاحب، جناب غلام نبی  
آزاد کے ذریعہ جو مسئلہ اٹھایا گیا ہے میں اس  
سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہوئے ہندوستان کے  
اور انسانیت کے دشمنوں کو اپنی پارلیمنٹ  
اور اپنے ایوان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ:

ہندو کا قتل ہے نہ مسلمان کا قتل  
ہے اے دشمنان ہندی انسان کا قتل ہے اس  
طرح کی واردتیں روزمرہ کا معمول بن گئی  
ہیں۔ جو باتیں ہمارے ساتھیوں نے کہہ دی  
ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش  
کرتا ہوں جو ظلم کے شکار ہوئے ہیں اور اپنے  
فرض سے کوتاہی کرنے والے یا فرائض کو نہ  
پہچاننے والے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ  
ملک کی آزادی کی رکھوالی اس طرح سے کی  
جاسکتی ہے جس طرح سے ملک کو آزاد کرانے  
کے لئے لوگوں نے دارورسن کا پھندا  
چوماتھا۔ جتنی قربانیاں ملک کو آزاد کرانے کے  
لئے

دی گئی ہیں، اس سے زیادہ قربانیوں کی ضرورت  
آن پڑی ہے، ملک کی آزادی اور خود مختاری کی  
حفاظت کے لئے ہم میں سے ساری پارٹیوں کے  
لوگ، اس سوگوار گھٹا کے لئے اپنے ان  
مظلوم، دنیا سے جانے والے لوگوں کا سوگ  
منارہے ہیں اور درندوں کی مذمت کر رہے ہیں۔  
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ  
بارڈر پر سیکورٹی فورس موجود ہے۔ پاکستان  
سے آنے والے یہ آتکواد آسمان سے تو نہیں  
ٹپکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ زمین سے چل کر آتے ہیں  
اور اگر ہم بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کی  
قسم کھاتے ہیں تو ہماری قسم کہاں ٹوٹ رہی  
ہے، ہم پر یہ سوالیہ نشان لگے بغیر نہیں رہ  
سکتا۔ میں کسی پر الزام نہیں لگاتا ہوں، لیکن میں  
کسی پر انگلی نہ اٹھاتے ہوئے ضرور کہنا چاہوں گا  
کہ پولیس کا کام ہے کہ شہروں میں فوج  
یا پیراملٹری فورسز کو آتکواد کے بارے میں  
خبردار کرنا۔ خفیہ ایجنسی کا یہ کام ہے، اسے یہ  
ضرور کرنا چاہئے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ  
اسے ضرور کر رہے ہوں گے، مگر بارڈر پر جو فورس  
لگی ہوئی ہے، جس بارڈر سے ہمارے دشمن  
ہمارے دیش میں داخل ہو رہے ہیں تو آخر وہ  
بارڈر پر کون سے کام میں لگے ہوئے

ہیں جس کی وجہ سے دشمن ہمارے ملک میں داخل ہونے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ دشمن یہاں اگر نفرت کا ماحول پیدا کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ سارے بارڈر پر نفرت کا ماحول پیدا ہو، ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں نفرت کا ماحول پیدا ہوگا تو تعصب کی گھٹائیں اٹھیں گی اور خون کا پانی بر سے گا۔ اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لئے ضروری کام مسلسل پرانی گورنمنٹ میں بھی ہوتے رہے ہیں یہ گورنمنٹ بھی کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اور آج دونوں ملک کے پردھان منتری سری لنکا میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سری لنکا میں دونوں پردھان منتری اکٹھے ہو رہے ہیں چونکہ جو دونوں جگہ کے عوام پریشان ہیں، یہاں کی عوام بھی پریشان ہے، پاکستان کی عوام بھی پریشان ہے۔ انسانوں میں مظلومیت جو سراہا رہی ہے، ظلم کے ذریعہ اس بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف بات چیت تک ہی یہ سارا معاملہ پھر مجھے لگتا ہے کہ محدود رہ جائیگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے اندر کوئی ایسی پاور ہے، کوئی ایسی شکتی ہے یا کوئی ایسا فیصلہ کرنے کا موڈ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کو دو دو چار میں بات سمجھائی جاسکے۔

پاکستان کیوں باتوں کے ذریعہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان مصلحت کے ذریعہ سمجھنے والا نہیں ہے، پاکستان خوش اخلاقی اور خوش کرداری کے ذریعہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ طاقت کی زبان سے آپکوبات کرنی ہوگی، اگر آپ طاقت کی زبان میں بات نہیں کریں گے تو ہم یقین کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتے ہیں:

مریض عشق پر لعنت خدا کی

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے کنٹرول ہو جائے گا ایسی حالت میں میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی ہمیں شوک منانا پڑتا ہے۔ پردھان منتری جی کی طرف سے بیان دینے کے باوجود ہم جس طرح سے لاغر ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، بے کس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، اس مجبوری میں ایک طرف ہم نیوکلیئر ہم کا مظاہر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف دشمن نے ہمیں چوہا اور بلی سمجھ لیا ہے۔ جب دشمن چاہتا ہے تب ہمیں للکار دیتا ہے، جب دشمن چاہتا ہے ہماری سرحدوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ گیارہ بارہ سال سے یہ سرد جنگ ہو رہی ہے اس میں معلوم نہیں کتنے ہندوستانیوں

کا خون پانی کی طرح سستا کر کے  
 بہا دیا گیا ہے۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ  
 جنگ کیجئے۔ مگرول پاور کے ذریعہ آپ اپنی  
 طاقت کے ذریعہ آپ کی نگوسیشن میں آپ کی  
 بولی میں گولی سے زیادہ طاقت ہونی  
 چاہئے۔ جس کی بنیاد پر آپ کا دشمن سہم کر جھکے  
 کے لئے مجبور ہو۔ مانوتا کوللکارا جانا ہندوستان  
 کے لوگوں کو اس طرح سے بے آبرو کرنا یہ کوئی  
 اچھی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں ہندوستان  
 امن کا داعی رہا ہے۔ ابھی غفران زاہدی صاحب  
 کہہ رہے تھے کہ ایک طرف نظریہ امن کی بات  
 ہو رہی ہے دوسری جنگ کا راستہ پیدا کیا  
 جا رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نظریہ  
 امن تو ہمارے پاس ہے اور اخبار جنگ پاکستان  
 کے پاس ہے۔ وہ تو پیپر میں بھی گفتگو کرتے ہیں  
 تو جنگ کی زبان میں جنگ نام رکھ کر کرتے ہیں۔

سر، جہاں تک ہندوستان اور جموں  
 کشمیر کے تحفظ کا سوال ہے اور اس کے وقار کا  
 سوال ہے میں اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ  
 میں کرنا چاہوں گا کہ غیروں کو میں گنگا و جمن دے  
 نہیں سکتے اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کشمیر  
 کو بڑپ کر لے گا، اگر ہندوستان میں افراتفری  
 پیدا کر کے ہندوستان

کو متزلزل اور غیر مستحکم کر دے گا  
 تو ہم تمام پارٹیوں کے لوگوں کو پارٹی سے  
 اوپر اٹھ کر پاکستان کے اس ناپاک خواب کو کسی  
 بھی قیمت پر شرمندہ تعمیر نہیں ہونے دینا  
 چاہئے اور بر حال میں اس کو کہہ دینا چاہئے کہ  
 غیروں کو مے گنگا و جمن دے نہیں سکتے ہم  
 دشمن کو گنگا جمن کا پانی دے نہیں دیں گے۔

غیروں کو یہ گنگا و جمن دے نہیں  
 سکتے ہم اہل وطن خاک وطن دے نہیں سکتے  
 کشمیر بڑی چیز ہے کیا دیں گے کسی کو ہم دیش  
 کے دشمن کو کفن دے نہیں سکتے اس لئے ہمیں  
 بڑی منت اور سماجیت کے ساتھ اپنے حکمرانوں  
 سے کہنا ہے جو لوگ آج اس سے سبکدوش  
 ہونا چاہتے ہیں ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ  
 ہیں۔ ہر قدم پر دیش کے تحفظ کے لئے تن من  
 اور دھن کے ساتھ پورا ہاؤس، پورا دیش آپ کے ساتھ  
 ہے۔ مگر خدا کے لئے آپ اپنی مردانگی  
 دکھائیے۔ آپ میدان میں آئیے آپ ہندوستان کی  
 توہین کرنے والے کی زبان کو لگام دیجئے  
 اور اگر ملک اسی طرح سے ٹوٹتا رہا، آتنکواد اسی  
 طرح سے بڑھتا رہا تو کل آنے والے دنوں میں  
 ملک کے عوام کسی بھی حکومت پر ہروسہ  
 کرنے کے لئے تیار نہیں ہو گے۔ بات ایک آئی تھی کہ

وہاں کے عوام کو ہتھیار دے دئے جائیں، میں سہمت ہوں اس بات سے، مگر عوام کو ہتھیار دینے سے پہلے ان کو ٹریننگ بھی دینی ہوگی، بغیر ٹریننگ کے عوام کیا ہتھیار چلا سکیں گے؟ پھر اگر عوام کو یہی اپنی حفاظت کرنی ہے تو پولیس کا ہتھیار کس کام کا ہے؟ پولیس سے ہتھیار ضبط کر لیجئے، اور عوام کو ہتھیار دے دیجئے، فوج سے ہتھیار چھین لیجئے اور عوام کو ہتھیار دے دیجئے۔ پیرا سیکورٹی فورس سے ہتھیار لے لیجئے اور عوام کو ہتھیار دے دیجئے۔ بارڈر سیکورٹی فورس سے کہہ دیجئے کہ گھر جا کر بیٹھیں اور عوام سے کہہ دیجئے اپنے گھروں سے بارڈر پر جا کر باحیثیت بارڈر سیکورٹی فورس کا کام کریں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اتنی فوج کس کے لئے ہے؟ اتنی پولیس کس لئے ہے؟ کیوں عوام ہاتھوں میں بندوق لیں گے۔ کیوں پبلک بندوق لے کر دشمنوں کا مقابلہ کریں؟ یہ دن اس وقت آئیگا جب ہمارے پاس فوج نہیں ہوگی، جب ہمارے بارڈر سیکورٹی فورس نہیں ہوگی۔ آج ہم ان معاملوں میں دنیا کی کسی بھی طاقت سے کمزور نہیں ہیں۔ عوام اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ اپنے دماغ کے ساتھ، اپنی صلاحیت کے

ساتھ، اپنی قابلیت کے ساتھ، اپنے تن من اور دھن کے ساتھ اور فورس پر فخر کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہونگے۔ مگر حضور مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ حکومت کو ایکٹیو ہونا چاہئے۔ صرف نعرہ لگانا، دعویٰ کرنا، دلیل کے نام پر کھوکھلے ہو جانا اس سے ملک نہیں بچایا جاسکتا ہے۔ سب لوگوں کو چنتا ہے ہم بھی اس چنتا میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، آپ آگے بڑھئے، مردانہ وار فیصلہ کیجئے، انشاء اللہ ہم بھی بزدل آپ کو ثابت نہیں ہونے دیں گے۔ ملک پورا آپ کے ساتھ رہے گا اور ملک کے وقار کا سودا کسی بھی دشمن کو کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جاسکتی۔ شکریہ۔  
□ ختم شد □

श्री जितेन्द्र प्रसाद ( उत्तर प्रदेश ) : सभापति जी, मैं अपने आपको संबद्ध करता हूँ कि जो विचार गुलाम नबी आजम जी ने और बहुत से माननीय सदस्यों ने व्यक्त किया। ... ( व्यवधान )

MR. CHAIRMAN: It is already 1 o'clock. I think, today, we will continue and skip the lunch.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal) : Sir, what about the statement?

MR. CHAIRMAN: That will come. It is in the agenda.

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मान्यवर, महीने भर में यह तीसरी दर्दनाक घटना घटित हुई है। यह बहुत ही एक गम्भीर चिंता का विषय है। मैं सिर्फ कुछ सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।



यह कहना चाहता हूँ कि यह भारत सरकार की, हमारे गृह मंत्रालय की एक बहुत बड़ी विफलता है कि बार-बार इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जब भी घटना घटित होती है हम सदन के अंदर आते हैं और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं कहना चाहूंगा गृह मंत्री महोदय से कि इन्होंने अनाउंस किया था कि फोर प्रॉग्नड अनका एक्शन प्लान होगा। उस एक्शन प्लान के तहत क्या हुआ? क्यों वह विफल हुआ? क्या वह एक्शन प्लान गलत था यह मैं आज जानना चाहूंगा।

श्री नगर गृह मुन्त्री महोदय तशरीफ ले गए थे। वहां पर जून के महीने में 24 तारीख को referring to the close and cordial relations between the Central Government and the State Government, Mr. Advani said, "Never before, in the current phase of militancy has the relationship been so friendly." जब इनको पूरा कोआपरेशन स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा था तब भी एक लोकलाइज्ड एरिया के अंदर बार-बार इस तरह की घटनाओं का होना बहुत हरी गंभीर चिंता का विषय है। किसी ने कहा इंटेलेजेंस का फल्योर है। किसी ने कहा कि लोकल पापुलेशन की मदद नहीं ली गयी। मैं सिर्फ सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि अगर एक छोटे से एरिया की सुरक्षा पूरी भारत सरकार की शक्ति नहीं कर सकती है तो इससे बड़ी विफलता इस सरकार की नहीं हो सकती है। मैं आज कहना चाहूंगा गृह मंत्री महोदय से कि ये आज सदन को आश्वस्त करें, सदन के द्वारा खास तौर से जम्मू-काश्मीर की जनता को आश्वस्त करें, देश की जनता को आश्वस्त करें कि अब इस घटना के बाद दुबारा इस प्रकार की घटना भी नहीं घटित होगी।

समाचारपत्रों ने, मान्यवर, यह छापा है कि जहां पर यह घटना घटित हुई वहां पर विलेज डिफेंस कमेटी गठित नहीं हुई थी जबकि गृह मंत्री महोदय के यह स्पष्ट निर्देश थे। वहां एक पुलिस चेक पोस्ट जो थी वह भी विदग्धा कर ली गयी थी जबकि गृह मंत्री के स्पष्ट आदेश थे कि वहां चेक पोस्ट बनायी जाए।

मैं यह पालिसी और हाट परस्यूट पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ। प्रो-एक्टिव और रिएक्टिव पालिसी भी सुनता रहा हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस एरिया में लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें और आज जो हम आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तान पर, आई0एस0आई0 पर, जिस पर भी, जो भी शक्ति हो जो भी इस कारनामों में लिप्त हों क्या हम अपने देश की जनता को और खास तौर से उस क्षेत्र

की जनता को सुरक्षित नहीं रख सकते। आज फिर दुबारा मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री आज यहां आश्वासन दें कि आज के बाद से दुबारा इस तरह की घटना घटित नहीं होगी। हम हर कदम उठाएंगे और पूरी भारत सरकार यह जिम्मेदारी ले कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। धन्यवाद।

**कुमारी निर्मला देशपांडेय ( नाम-निर्देशित ) :** सभापति महोदय, भाइ गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा, उसके साथ वहां पर डोडा में जो हुआ, उसके लिए अफसोस प्रकट करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि डोडा एक ऐसा जिला है जिसके गांव-गांव और शहर-शहर से हम लोगों का परिचय है। इसलिए कुछ बातें मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि किसी भी हाल में ऐसी घटना को लेकर पर उस जिले में जो भाईचारा है मुसलमानों के बीच में- हमेशा जिस भाईचारे को देखकर बहुत खुशी होती है- उस भाईचारे को बनाए रखने की तरफ ध्यान देना जरूरी है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपके द्वारा कि आज जब दोनों प्रधान मंत्री मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, उसी वक्त इस घटना का होना —क्या इसके पीछे कोई और संकेत नहीं है? क्या कोई ऐसी ताकतें हैं जो दोनों देशों के बीच में दोस्ती नहीं होने देना चाहती हैं और उन ताकतों के इशारों पर ऐसी घटनाएं होती हैं? इस पर भी हमें गौर करना चाहिए।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहती हूँ सरकार और जनता दोनों को अलग करना चाहिए। पाकिस्तान की जनता हिन्दुस्तान के साथ दोस्ती चाहती है, भाईचारा चाहती है, इस बारे में हमें कोई शक-शुबह नहीं है। हमारे वहां के सैकड़ों दोस्त हर जगह मीटिंग कर रहे हैं, जलूस निकाल रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं कि हिन्दुस्तान के साथ हमें अपने मसलों को बात-चीत से हल करना चाहिए। किसी हालत में लड़ाई नहीं होने देना चाहिए। [जंग नहीं, हमें अमन चाहिए] यह नारा चारों तरफ वहां कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कुएटा में गूंज रहा है। यह मैं आपके द्वारा इस सदन को बताना चाहती हूँ। इसलिए इस वक्त जरूरत है कि दोनों मुल्कों के लोग, दोनों मुल्कों के दानिशवर, दोनों मुल्कों के कलाकार, दोनों त.मुल्कों के सोचने —समझने वाले लोग मिलें, भारत —चीत करें और अपनी-अपनी सरकारों से कहें कि गलत कदम मत उठाएं। इसकी तरफ ध्यान देना मैं जरूरी समझती हूँ। मैं आपके द्वारा इस सदन को बताना चाहती हूँ कि हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि किसी

भी हालत में दोनों मुल्क जंग की तरफ न जाए, जब कि दुनिया की कुछ ताकतें हमको लड़ाना चाहती हैं, बर्बाद करना चाहती हैं और हमारी तबाही को देख कर सिर्फ अपनी हकूमतों चलाना चाहती हैं। इससे हमें सावधान, सतर्क हो जाना चाहिए और दोनों मुल्कों के अवाम के मेल-जोल का, भाईचारे को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

महोदय, यह वक्त है कि जब भावनाओं में बह कर किसी भी तरह क गलत कदम की तरफ हम न जाएं। यह जमाना युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है, अहिंसा का है। धन्यवाद।

**श्री सभापति :** श्री कुलदीप नैयर।

**SHRI KULDIP NAYYAR (Nominated):** Chairman, Sir, this is a very serious matter. And I think we should ponder over it with all our equanimity and balance. I do not think that Pakistan is going to stop proxy war. Whenever I have gone there and talked to lots of people at various levels, I found them saying, 'Though I do not think that that is a reply because if something is being done from here, they should also do that. That is neither here nor there. The point I am trying to make is that Kashmir in Pakistan...

**SHRI GHULAM NABI AZAD:** I think this should not form part of the record.

**MR. CHAIRMAN:** Please ..... (*Interruptions*)... What Mr. Ghulam Nabi Azad .... (*Interruptions*).

**SHRI KULDIP NAYYAR:** I just mentioned the name. Did I say .... (*Interruptions*).

**MR. CHAIRMAN:** Please sit down. कुलदीप नैयर जी एक मिनट बैठिए। .... ( **व्यवधान** ) देखिए, जैसा गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा ... ( **व्यवधान** )

**SHRI GHULAM NABI AZAD:** This should not form part of the record.

**MR. CHAIRMAN:** I agree.

\*Expunged as ordered by the Chair.

**SHRI KULDIP NAYYAR:** I tried to bring here what they were saying there. If you do not want to hear .... (*Interruptions*)

**श्री सभापति:** देखिए जैसा गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा जो सदन का माहौल है उस बात में जो वह बात कही है वह हटा दी जाएगी। ... ( **व्यवधान** )

**श्री कुलदीप नैयर :** महोदय, मैंने सिर्फ... ( **व्यवधान** )

**श्री सभापति :** देखिए, अब आप उस बारे में मत कहिए।... ( **व्यवधान** )

**SHRI KULDIP NAYYAR:** I tried to bring you what they are saying. Whether it is a propaganda; I just brought it to your notice, did I support it or anything like that?

**MR. CHAIRMAN:** It was not required.

**श्री कुलदीप नैयर :** आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए ... ( **व्यवधान** ) इस तरह की बातों से तो बात बनेगी नहीं... ( **व्यवधान** )

I cannot really help you because you are... (*Interruptions*)

**SHRI SATISHCHANDRA SITARAM PRADHAN:** We don't want to hear you. (*Interruptions*)

**SHRI KULDIP NAYYAR:** Mr. Chairman, Sir, I have a right to speak. If this is going to be the atmosphere, how can I speak? (*Interruptions*) What kind of allegations they are making? (*Interruptions*)

**SHRI K.R. MALKANI (Delhi):** The solemn atmosphere has been badly disturbed by you. (*Interruptions*)

**SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh):** You clearly said that you subscribe to the statement that it is the ... (*Interruptions*)

**MR. CHAIRMAN:** Those words have been deleted. Those words have been expunged. I agree with Shri Ghulam Nabi Azad. On this question, the whole atmosphere was different. There is

solidarity. The speeches made by many Members here have been very good, reflecting the unity of the country. This is happening for the first time, perhaps. But it is a very healthy sign. Therefore, please keep up that atmosphere. There should be impartiality. More than impartiality, unity is required.

SHRI GHULAM NABI AZAD: That is right, Sir.

SHRI KULDIP NAYYAR: Thank you, Mr. Chairman.

Now, what is Pakistan trying to do there? We have, more or less, eliminated militancy in the Valley. Despite everything, they have not been able to create an atmosphere whereby they could create distance between the Hindus and the Muslims. In the Jammu Region, in the higher reaches, they are trying to communalise the situation. Not only that. Although militancy had been suppressed there, they are trying to build a base on this side.

Knowing all these things—I think, the hon. Home Minister knows it much better than me—what are we going to do for the future? Even though we do our best to stop these people at the border—which, probably, we are doing—still, there would be some kind of infiltration taking place. I think, these people who are coming to Doda are coming through Anantnag. This is my information. Maybe, I am wrong.

The point is, we have to, some day, take up this topic seriously, with not really the Government only, but also with the intellectuals in Pakistan, with the newspapermen in Pakistan. Without discussing this matter with them, we will not be able to stop this, whatever steps we take. We should take some steps. No doubt about it. My humble suggestion is that the human rights organisations from this side and the human rights organisations from that side could, probably, make some kind of a front. People from both sides could make some kind of a joint front and see what is

happening. (*Interruptions*) His is a suggestion I am making. Maybe, at the people level, we are doing. Now, Mr. Chairman, ...

MR. CHAIRMAN: Over? Shri Pranab Mukherjee.

SHRI KULDIP NAYYAR: Not over. (*Interruptions*) Sir, this is a very strange kind of thing. Either you give me permission, or, you don't give me permission. I am not speaking further.

MR. CHAIRMAN: No, no. (*Interruptions*) I thought you had completed. (*Interruptions*)

SHRI KULDIP NAYYAR: This is not fair. So, I am not speaking. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: All right. Mr. Pranab Mukherjee. (*Interruptions*)

SHRI KULDIP NAYYAR: I do not wish to say. But how can the Chairman be partial? (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please don't say that. (*Interruptions*) I thought you had completed.

SHRI KULDIP NAYYAR: No, No. How can you give permission to others?

MR. CHAIRMAN: Now, if you have not completed, please complete.

SHRI KULDIP NAYYAR: I have not completed. Did you ask me 'have you completed'?

MR. CHAIRMAN: Yes. I thought you had completed. Please complete.

SHRI KULDIP NAYYAR: What about the time taken by them? Ten minutes were taken away by interruption; and then you shut me up.

MR. CHAIRMAN: Kindly complete your speech now.

SHRI KULDIP NAYYAR: Sir, as I started saying, we are passing through a very critical period: not only in this country, but in Pakistan also. Pakistan, after acquiring the bomb, has adopted a war-like posture. Now, can we think of 'hot pursuit' today? It is not possible

because one thing would lead to another. What we have to do is this. Through talks at various levels, at the intellectual level, at the people level, as I said, at the level of the human rights organisations, which we are trying to do, maybe, we would be able to do something. I am not saying that it is going to be easy, because Kashmir still gives Pakistan its ethos. There is nothing else which holds them together. So, my request to the House is: please consider this as an issue which belongs to all of us, to the country. There may be some people who may differ with you on something. But that does not mean that when it comes to something serious, there is any kind of division in this country or in this House. We are all with you on this point. But the only thing is that your approach may be different from that of ours. That is all.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Sir, while associating myself with the observations made by Mr. Ghulam Nabi Azad and many others, I most humbly submit that we are anguished. If the problem would have been merely that of law and order, killing of some persons, the discussion would have taken place in a different context. The problem has more than one dimension. All of us are fully aware of the gravity of the situation because all these incidents of militant activities are backed by cross-border logistic support. International terrorism is going to be one of the gravest menaces to peace and security in the post cold-war era.

When we met you in your chamber. Sir, as we understand, the whole purpose was to express the concern of the House over the way the terrorist activities, militant activities, are being supported by some country, particularly when we have become the victim, to convey the sense of our concern in the context of the discussion which is taking place between the two Prime Ministers, at Colombo. Though the SAARC has nothing to do with bilateral issues, taking the opportunity of the presence of two Prime

Ministers, when they are meeting there definitely, they are going to discuss about it. We wanted to strengthen the negotiating position of our Prime Minister by expressing our own concern over the ever increasing terrorist activities in this country. The Doda incident is a manifestation of that.

I do entirely agree with the observations made by many Members that we should not vitiate the atmosphere because the situation is really crucial. There may be interested parties who want to vitiate the situation more even when the talks are going on. I do not expect that there will be a very positive outcome of the talks; it may not happen. But, at the same time, we have no option but to initiate the talks, to have a dialogue and to have some sort of understanding so that we can live in peace in this whole sub-continent itself. Therefore, I am not going to make any observations on this issue.

Most respectfully, through you, I would submit to the Government. The Home Minister is present here. He will definitely give his own response. In what manner he will like to respond, it is for him to decide. But, please convey the sense of the House, the feelings of the Members who have participated in this debate, to the Prime Minister in Colombo, so that he can keep our concern at the back of his mind while he is having his talks and negotiations with his counterparts in Colombo. This is my most respectful submission, through you, Sir, to the Government.

MR. CHAIRMAN: I hope the Government will convey to the Prime Minister the unanimous concern and support of the House for his negotiations with the Prime Minister of Pakistan.

Mr. Advani, do you want to speak on this? The next statement is yours.

DR. M.N. DAS (Orissa): Mr. Chairman, Sir, I want to say...

MR. CHAIRMAN: There are a number of others also. It is already 1—130 P.M. now.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Sir, shall we meet after lunch?

MR. CHAIRMAN: There is no lunch-break now.

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** सभापति जी, मैं आभारी हूँ श्री गुलाम नगी आजाद का और विभिन्न दलों के सभी प्रतिनिधियों का जो इस विषय पर बोले हैं, उन्होंने जम्मू-कश्मीर की परसों की घटनाओं के संदर्भ में कई बातों को एक साथ व्यक्त किया है, जो उग्रवाद निरीह नागरिकों की जानें ले रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके बारे में वेदना और व्यथा अभिव्यक्त की है।

उसके कारण डोडा जिले में आज जो असुरक्षा का वातावरण पैदा हो गया है, उसके बारे में सबने चिंता प्रकट की है। सभी लोगों ने एक स्वर से यह कहा कि पाकिस्तान के इस प्रॉक्सी वार को रोकने के लिए और उसमें उसे पराजित करने के लिए, हमारे आपस में चाहें जितने भी राजनीतिक भेद हों, हम सब एक हैं, सदन भी एक है और देश भी एक है। यह भावना अनेक सदस्यों ने प्रकट की कि इस सरकार के आने के बाद भी इस प्रकार की 3 घटनाएं हुई हैं— एक ऊधमपुर में सरकार ने जो प्रतिक्रिया प्रकट की कि हम इसके बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। तो सदस्यों ने पूछा कि क्या वह कार्यवाही फेल हो गई या कार्यवाही हुई नहीं तो इस विषय में सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में आशंकाएं और संदेह प्रकट किए जा रहे हैं। मैं यह मानता हूँ कि कुल मिलाकर सभी सदस्यों ने, एक माननीय सदस्य को अपवाद के रूप में छोड़कर जिन्होंने एक प्रकार से पाकिस्तान के इस तर्क को दोहराया जो वह वर्षों से देता रहा है कि हमारे यहां कोई प्रॉक्सी वार नहीं हो रहा है, हम तो वही कर रहे हैं जो कि हिन्दुस्तान हमारे यहां करता है, जो कि सरासर झूठ है, गलत है। यह बात उनको कई बार कही गई है और हमसे जब विदेशी लोग मिलते हैं तो इस विषय में चर्चा करते हैं। वे भी यह मानते हैं कि कराची का दोष भारत पर डाल देना किसी प्रकार से तथ्य नहीं है। एक अपवाद को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों ने ये चारों बातें कही हैं और मैं इसके लिए सदन को बधाई देता हूँ।

महोदय, जो बात आपने कही और श्री प्रणव मुखर्जी ने कही मैं प्रधानमंत्री जी से संपर्क करने की कोशिश

करूंगा। वैसे तो वहां चर्चा चल रही हरेगी, मैं कह नहीं सकता लेकिन आज की जो बहस हुई है, उसका एक सही संदेश जाएगा विश्व के लिए, देश भर के लिए और मेरे लिए भी और मेरी सरकार के लिए भी।

महोदय, मैं इतना कह सकता हूँ कि आज जाक जम्मू-कश्मीर की स्थिति है वह लगभग 9 सालों से है। यह समस्या प्रॉक्सी वॉर की उग्र रूप में 1989 से शुरू हुई और 1990 में यह शिखर पर पहुंच गई थी और 1989 से लेकर लगातार इन 9 सालों में कई सालों तक फोकस था कश्मीर की घाटी और कश्मीर की घाटी पर फोकस रखकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी कि वर्षों तक जम्मू-कश्मीर में कोई यात्रा नहीं जाते थे, जाने का साहस नहीं करते थे। मैंने 1989 के फिगर्स देखे तो पता लगा कि 1989 में जम्मू-कश्मीर में 5 लाख के करीब लोग गए थे और अभी 2 साल पहले 1996 में देश भर के और विदेशी यात्रियों की कुल संख्या 300 और 400 के बीच थी। यह स्थिति हो गई थी। पहले जब हिन्दुस्तान भर के लोग फिल्में बनाते थे तो उन्हें लगता था कि सीनिक ब्यूटी के लिए श्रीनगर चलो, पहलगांव चलो, गुलमर्ग चलो। लेकिन वर्षों से फिल्म वालों ने वहां जाना बंद कर दिया था। इस साल पहली बार स्थिति में परिवर्तन आया और परिणाम यह हुआ है कि वहां पर इस साल हजारों लोग श्रीनगर गये हैं, पहलगांव गए हैं, गुलमर्ग गए हैं। स्थिति का परिवर्तन है। कभी-कभी तो यह भी लगता है कि बहुत निराश हो गए हैं मिलिटेंट्स जो घाटी में काम कर रहे थे। हां, उन्होंने अपना ध्यान इस तरफ लगाया है तो हमारा रिस्पांस भी उसी प्रकार से होना चाहिए। उन्होंने डोडा, ऊधमपुर, पुंछ-राजौरी पर कंसन्ट्रेट किया है और उस केसन्ट्रेटेड ऐफ़्टर मे हम उनको ठीक उत्तर दें सकें, यह जवाबदारी सरकार की जरूर है। और मुझे तो फिगर्स कभी-कभी मिलती हैं, तो पिछले जुलाई के महीने तक शायद 388 मिलिटेंट जिनमें से 65 फॉरेन मर्सनरीज थे उनको मारा गया। 545 मिलिटेंट गिरफ्तार हुए हैं। Process of attrition. और इसीलिए मुझे याद है कि मैं कभी—कभी पेजाब जाता था तो लगता था कि स्थिति सुधरेगी नहीं, स्वयं भी निराश होता था। लोग शाम को घर ससे निकल नहीं सकते थे, शहरों में, गांवों में ऐसी स्थिति थी। लेकिन और सदस्य ने भी बात कही और कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं है, जनता का साथ नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसा कहना उनके साथ अन्याय होगा।

यह स्थिति आज नहीं है। एक फेस था टेरोरिज्म का जब लगता था कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में से, उनका मुकाबला कोई नहीं कर रहा है वहाँ की पुलिस में। आज वह स्थिति नहीं है। और वह स्थिति ने होते हुए भी मैं यह नहीं कहूँगा कि ऐसे तत्व नहीं हैं प्रशासन में या पुलिस में कि जिनके बारे में हमको सावधानी बरतनी चाहिए लेकिन पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को या पूरी पुलिस को इस प्रकार से और उनको कहना कि वह विश्वास योग्य नहीं हैं, मैं समझता हूँ कि उनके प्रति भी न्याय करना नहीं होगा और वहाँ की स्थिति को भी संभालने में यह एप्रोच सहायक नहीं होगा। मेरी मान्यता है कि आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज यह अल्टीमेट नहीं हैं सफलता के लिए। पंजाब में भी अगर सफलता मिली तो उसमें प्रमुख भूमिका वहाँ के प्रशासन की और वहाँ की पुलिस की थी उससे भी ज्यादा सा भूमिका थी वहाँ की जनता की जिन्होंने उग्रवादियों को सहयोग देना पूरी तरह से बंद कर दिया और मैं मानता हूँ कि जम्मू-कश्मीर इस दिशा में बढ़ रहा है। जम्मू काश्मीर में यह सोचना कि हमको कोई जानकारी नहीं मिलती, इंटेलीजेंस नहीं देता, ऐसा नहीं है। हमारे पिछले दिनों में जितनी सारी गिरफ्तारियाँ वहाँ पर हुई हैं। जितना कुछ हम कर सके हैं उग्रवादियों के खिलाफ खास करके घाटी के इलाके में तो वह प्रमुख रूप से वहाँ कि जनता से जो हमको जानकारी मिलती रही है उसके आधार पर करते रहे हैं और इसलिए वहाँ की स्थिति को सही परस्पेक्टिव में पहचान करके, उसके आधार पर उसको डील करना इस सरकार का संकल्प है और मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ और मैंने कभी भी किसी स्टेज पर यह नहीं कहा कि कोई घटना ही नहीं घट सकती। ऐसा संभव नहीं है। मैं अभी-अभी यहाँ बैठा हूँ, तो हमारा मंत्रालय सूचना भेजता है कि गोहाटी में फलाने स्थान पर नरहरि डिस्ट्रिक्ट, बरामा वहाँ पर एक बम विस्फोट हुआ है जिसमें 8 लोग मारे गए हैं। अब यह जो घटनाएं हैं, यह घटनाएं ऐसी हैं कि अधिक से अधिक सावधानी बरतो, अधिक से अधिक काम करो तो भी इन घटनाओं को पूरी तरह से रोक सकना संभव नहीं है। यहाँ पर इस दिल्ली के शहर में जहाँ पर किस का राज था, किस का राज नहीं था इसका सवाल नहीं है, लेकिन, दिसम्बर 1996 से लेकर के आज तक 40 बम विस्फोट हुए हैं- दिल्ली और आसपास। मुझे तो इसी बात का समाधान है कि 40 में से 36 के बारे में जो अपराधी थे उन अपराधियों को दिल्ली पुलिस पकड़ पाई, यह बहुत बड़ी बात है। हम अपनी तरफ से इस मामले में देश के सहयोग के साथ, जनता के सहयोग के साथ हम यह संकल्प किए हुए हैं कि हम प्रोक्सी वार

मेहम देश के दुश्मनों को पराजित करेंगे, हर हालत में पराजित करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सम्भव है, ऐसा नहीं है कि यह सम्भव नहीं है। योजनाएं कुछ बनाई हैं और आजमी साहब ने कुछ बातें कहीं, बहुत अच्छी मुझे लगती थी। मैं मन में सोचने लगा कि मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को प्रो-एक्टिव होना चाहिए रि-एक्टिव नहीं होना चाहिए मैं जानता हूँ कि उसकी कितनी आलोचना हुई और प्रो-एक्टिव कहने के बाद किसी ने सवाल पूछा कि इसका मतलब होट परसूट है। मैंने कहा नहीं है, इसका मतलब होट परसूट नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आज की परिस्थिति में अन्यथा होट परसूट या परमिटिड है।

लेकिन होट परसूट की कल्पना नहीं करती क्योंकि उसकी ग्रेविटी हम समझते हैं। लेकिन प्रो-एक्टिव का मतलब यह है कि आपको स्ट्राइक करे मिलिटेंट उसके बाद आप जाकर के उसका पकड़ें, उसके बजाए आपकी इंटेलिजेंस एजेंसिज आपकी जनता का सहयोग उसके आधार पर आप पहले पता लगा करके आप प्रो-एक्टिव होकर के उनके ऊपर एक्शन लें, यह है प्रो-एक्टिव। लेकिन उस एक शब्द को लेकर जैसे मानो पता नहीं क्या अनर्थ कह दिया, कितना कुछ कहा गया। कुल मिला कर देश का माहौल होना चाहिए कि देश का दुश्मन किसी भी रूप में हो और हम पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान की चिंता न करें लेकिन अगर पाकिस्तान प्रॉक्सी वार करने में कुछ भी सफलता पाता है तो उसका कारण थोड़ी बहुत मात्रा में वे इनफिल्ट्रेटर्स हैं जिनको कि रोकना चाहिए सीमा पर, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में जजो देश के अलग-अलग भागों में उनको समर्थन देने वाले लोग हैं और उनको समर्थन देने वाले लोगों के बारे में अगर यह सरकार कठोर कार्यवाही करती है तो उस समय जिस प्रकार की आलोचना होती है, उस आलोचना की ही मुझे चिंता है और वह आलोचना नहीं होनी चाहिए। देश की सुरक्षा का यह तकाजा है कि हम देश के दुश्मन खांस कर भीतर अगर कोई है तो उसकी पूरी चिंता करें, उसके बारे में किसी भी प्रकार की नरमी न बरतें, यही मेरा निवेदन है।

मौलाना अबुदुल्ला खान आजमी : घर का मेदी ही लंका ढाता है। बिलकुल सही है उनको पकड़ना चाहिए।

{مولانا عبید اللہ خان اعظمی: گھر کا بھیدی  
 بی لنکا ڈھاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے ان کو پکڑنا  
 چاہئے۔}

MR. CHAIRMAN: The next item is statement by Shri L.K. Advani on the deportation of certain people from Mum-bai by the Maharashtra Government. Seeing the way the debate has gone on now, I hope that Members would put their questions one after another and that they will allow each other to speak and then the hon. Minister will reply.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, in respect of the earlier subject, I would like to inform the House कि उस डोडा की घटना के संदर्भ में आज प्रातः काल हमारे गृह सचिव श्री बी०पी० सिंह, बी०पी०एफ० के डायरेक्टर जनरल श्री राम मोहन और मिलिटरी ऑपरेशन्स के एडीशनल डी०जी० मेजर जनरल सिंह, ये तीनों वहाँ पर गए हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए और आगे क्या कार्यवाही करनी है, इसको देखने के लिए। तीन कंपनीज और उस क्षेत्र में भेज दी गई हैं तुरंत।

MR. CHAIRMAN: Now, the statement by Shri Advani.

**STATEMENT BY MINISTER**  
**Deportation of certain people from Mumbai by**  
**Government of Maharashtra**

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Sir, various reports have appeared in media regarding the deportation of Bangladeshi nationals from Maharashtra. Maharashtra Government has informed that they had despatched three parties of deportees on 20th, 21st and 22nd July to West Bengal with 24, 34 and 38 deportees respectively.

According to the information furnished by the Government of Maharashtra, an elaborate procedure is followed for detection, identification, and deportation of illegal Bangladeshi tminigrants. The suspected foreigners are given adequate opportunity to produce proof of their

national status by way of birth certificate, school leaving certificate, ration card, electoral identity card, domicile certificate etc. In the event of failure to produce any ..such document, the suspect is charged under the relevant provisions of the Passport (Entry into India) AcV rules and the Foreigners Act, and produced before a metropolitan magistrate who gives sufficient opportunity to such persons for producing proof of nationality. It is only in cases where no such evidence is produced to the satisfaction of the Court that the Court grants permission to the competent authority for deportation of such persons. The competent authority then issues the deportation order under Section 3(2)(c) of the Foreigners Act.

The powers of the Central Government under the Foreigners Act, 1946, Passport (Entry into India) Act, 1920 and the rules and orders framed thereunder have been entrusted to the State Governments/UTs with their prior consent, under Articles 25&239 of the Constitution. These powers *inter alia* include the power to detect and deport the foreign nationals staying illegally.

The procedure for detection and deportation of illegal Bangladeshi immigrants mentioned in para 2 above is being followed by Maharashtra and other States based on which such illegal immigrants are regularly being deported. Maharashtra Government has further informed that the illegal immigrants who were being taken for deportation through Indo-Bangladesh border in West Bengal were detected to be illegal immigrants in accordance with the above mentioned procedure. It has also been informed that the police parties escorting these deportees were carrying with them deportation order issued by the Deputy Commissioner of Police, Special Branch-I, CID, Mumbai First and third parties of 24 and 38 deportees respectively were handed over to the West Bengal Police at the instance of local district administration. The second party of 34

†[ ]Tratuitleration in Arabic Script